मिलियन टन प्रति वर्ष है । वर्ष 1990 के अक्तूबर महीने के दौरान कच्चे तेल का देशी उत्पादन 2.558 मिलियन टन था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् में पदाधिकारियों की नियुक्ति

1291. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजोत सिंह अरोड़ा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कई वर्ष पहले केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का गठन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद् का गठन कब किया गया था और इस परिषद् के गठन का मुख्य मूल उद्देश्य क्या था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस परिषद् के पदाधिकारियों का विहित नियमों के अनुसार चुनाव करने के बजाय इसके सभी पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया है ;

(घ) यदि हां तो परिषद् के पदाधिकारियों की नियुक्ति निर्वाचन पद्धति से नहीं करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या यह भी सच हैं कि पदाधिकारियों के लम्बे समय तक पद पर बने रहने के कारण उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या हैं और परिषद् में कब तक चुनाव कराए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (प्रो० शकीलुर रहमान) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अनुसार केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का गठन इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने अर्थात् होम्योपैथी में शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करने, होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर का रखरखाव करने और उससे संबंधित मामले को देखने के लिए मनोनीत सदस्यों सहित अगस्त, 1974 में किया गया था ।

(ग) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 3 के खंड (1) (ग) के उपबंध के अनुसार, यह परिषद मनोनीत सदस्यों के साथ गठित की गई थी और इस अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया था ।

(घ) धारा 3 के खंड (1) (क) और (ख) के अनुसार गुजरात राज्य और कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़कर इस परिषद् के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है । चुनिन्दा सदस्यों के नामों को अधिसूचित कर दिया गया है ।

(ङ) इस मंत्रालय में केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् में अनियमितताओं के बारे में "राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा" नई दिल्ली से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् से उस पर पैरावार टिप्पणियां मांगी गई हैं जिसकी प्रतीक्षा है ।

छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण दिया जाना

1292. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **मानव संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार छात्रों को अनुदान और छात्रवृत्तियां देने की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर

उनको उच्च शिक्षा के लिए ऋण दिये जाने की प्रणाली अपनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस योजना बनाई है ; और

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) उच्च अध्ययन के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति की मौजूदा योजना के स्थान पर ऐसे छात्रों को ऋण देने की योजना प्रतिस्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

शिक्षा पर वार्षिक-व्यय

1293. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा पर किए जाने वाले कुल वार्षिक-व्यय का एक बड़ा हिस्सा उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान शिक्षा पर कुल कितना धन व्यय किया गया है और उसमें से कितना धन उच्च शिक्षा पर खर्च किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार परिनियत संकल्प को ध्यान में रखते हुए 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए भविष्य में उपरोक्त व्यय के अनुपात में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) उच्चतर शिक्षा पर होने वाला व्यय वर्ष 1989-90 में सामान्य और तकनीकी शिक्षा के संशोधित प्राक्कलनों का 24.1 प्रतिशत होता है ।

(ख) वर्ष 1987-88 में सामान्य और तकनीकी शिक्षा पर 1205.25 करोड़ रु० व्यय हुआ था जिसमें से 335.58 करोड़ रुपये उच्चतर शिक्षा पर खर्च किए गए थे । वर्ष 1988-89 के लिए तदनुरूपी आंकड़े क्रमश: 1598.63 करोड़ रुपये और 346.16 करोड़ रु० थे । वर्ष 1989-90 के लिए तदनुरूपी संशोधित प्राक्कलन 1522.08 करोड़ रुपए और 367.27 करोड़ रुपए थे ।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने को उच्च प्राथमिकता दी गई है । प्रारंभिक शिक्षा पर केन्द्रीय सरकार का परिव्यय जो 1986-87 (वास्तविक) 33.15 करोड़ रुपए था से बढ़कर वर्ष 1989-90 (संशोधित प्राक्कलन) में 212.10 करोड़ रुपए हो गया है ।

संस्थाओं द्वारा सरकारी अनुदान का समुचित उपयोग किया जाना

1294. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **मानव संसाधन** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के संबंध में अनेक शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक गैर-सरकारी संस्थाओं को इस संबंध में सरकार से अनुदान प्राप्त हो रहा है किन्तु वे उसका ठीक से उपयोग नहीं कर रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध जांच करने के